

in terms of import duty revision to 220 per cent is sufficient to save this industry from closure;

(b) whether at the two years old level of 220 per cent import duty the Small re-rollers were existing;

(c) if so, whether the raw material used by these small re-rollers (i.e. Stainless Steel Rounds/Billets etc. manufactured by Public Sector Units) was not available at Rs. 17/- per Kgs. as compared to the current price of Rs. 24/- and whether the import of Stainless Steel Sheets at that time was not banned for the manufacture of utensils; and

(d) if so, how Government propose to safeguard these small re-rollers when the duty has been fixed at 220 per cent.?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). In fixing the rate of duty on stainless steel plates, sheets and strips used for unspecified purposes at 220 per cent, the Government had kept in view, *inter alia*, the interests of stainless steel re-rollers as also of the indigenous producers of stainless steel. It is true that the prices of indigenously produced stainless steel rounds/billets, etc. have increased but the prices of imported stainless steel sheets, have also increased, during the same period correspondingly or perhaps even to a greater degree. As regards Import Policy, stainless steel sheets have been allowed to manufacturers of utensils on ad-hoc basis since October, 1975. The Import Policy for 1977-78 also provides for the requirements of the manufacturers of utensils just as the import policy for the preceding year 1976-77 did.

Civil Aerodrome at Agra

5321. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state whether in view

of the inconvenience caused to the public because of the restrictions on entry to the Kharja Civil Aerodrome at Agra, Government are considering the desirability of having a separate gate for the restricted entry of the public?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTAM KAUSHIK): The Indian Airlines enclave at Kharja aerodrome at Agra is located within the premises of the Air Force Technical Area. The existing procedure for entry/exit to the Indian Airlines enclave is laid down keeping in view the security of the Air Force installations. Considering the layout of the Air Force complex and the location of the civil enclave within, there is no possibility of providing a separate gate for entry/exit to the Indian Airlines enclave without interfering with the security arrangements.

रक्षा के मनकों का आयात

5322. श्री बृज भूषण तिवारी :

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या बाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशों से रक्षाभण के छोटे मनकों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों से उनके आयात किये जाते हैं और वर्ष 1974-75, 1975-76, और 1976-77 में वर्षवार कितनी मात्रा में कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(ग) विदेशों में स्थित उन अधिकृत फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे उक्त मनकों का आयात किया जाता है और इनका आयात करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) जी हाँ ।

(ख) (1) जिन देशों से ये मनके आयात किये जाते हैं उनके नामों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(2) 1974-77 की अवधि के दौरान जारी किये गये आयात लाइसेंसों का वर्षवार मूल्य इस प्रकार है :

1974-75	-	7,500 रु०
1975-76	-	20,000 रु०
1976-77	-	12,500 रु०

(ग) (1) विदेशों में इन मनकों की सप्लाई करने वाली फर्मों के सम्बन्ध में सरकार के पास जानकारी नहीं है ।

(2) 1974-77 की अवधि के दौरान निम्नलिखित फर्मों/व्यक्तियों को लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट दिये गये :

1. मैक्स भद्रानी गिरी एण्ड सन, हरिद्वार;
2. मैसर्स नारायण दत्त प्रभु दयाल, वाराणसी;
3. श्री दीना नाथ, वाराणसी;
4. श्री मौनी बाबा, वाराणसी;

(2,500 रु० के लिये सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी किया गया था) ।

5. भारत साक्षु समाज नई दिल्ली ।

हल्दीघाटी प्रंचल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

5323. श्री लालजी चाई : क्या पर्यटन और नागर बिमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार का विचार महाराणा प्रताप की स्मृति में हल्दीघाटी प्रंचल का केन्द्रीय सहायता के साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का व्योम क्या है ?

पर्यटन और नागर बिमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : राज्य सरकार का हल्दीघाटी का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है । इसमें सम्बद्ध स्कीम ये है :— मड़कों का विकास; चेतक चवतरे में मुधार; छतरियों का निर्माण; तथा इस क्षेत्र का सौंदर्यवर्द्धन । राज्य सरकार से पता चला है कि उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन पर 5.29 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है । केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने हल्दी घाटी पर्यटक काम्प्लेक्स के सौंदर्यवर्द्धन के लिए एक लाख रुपए का योगदान किया ।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार को सरकारी नियन्त्रण में लेना

5324. श्री मुबराज : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भूतपूर्व श्रम मंत्री तथा औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार ने 1976-77 में भूतपूर्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय और केन्द्र सरकार के उद्योग सचिव को इस द्वाारा के